SI. No.	Name of the States4	JTs 96	1995-87.05
14.	Orissa		
15.	Punjab		17.74
16.	Rajasthan		3.56
17.	Tamil Nadu		43.97
18.	Tripura		3.58
19.	U.P. (Hills)		7.90
	U.P. (Plains)		130.82
20.	West Bengal		53.91
21.	Others		4.62
	TOTAL :		715.86

पशुपालन और डेयरी उद्योग

951.**श्री गोपाल सिंह ली सोलंकी**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या देश के पुशपालन और डेयरी उद्योग को इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं किया गया है कि आम जनता को उनके उत्पादों का ठीक-ठीक विवरण किया जा सकें,

(ख) यदि हां,तो क्या सरकार ने हाल ही के वर्षो में पशुपालन और डेयरी संबंधी योजनाओं को शुरू करने के लिए उपर्युक्त स्थानों का पला लगाया हैं ;

(ग) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(घ) इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) से (घ) पशुपालन का विषय है । पशुपालन और डेयरी के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से यह विभाग विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों की सहायता प्रदान कर रहा हैं ।

केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई विशिष्ट विपणन योजना नहीं है जो कि स्थानों की पहचान करने तथा डेयरी उत्पादों के विवरण से संबंध रखती हो । स्थान तथा सार्वजनिक वितरण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की हैं ।

Fanners' Welfare Fund

952. SHRI JALALUDIN ANSARI:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRIMATI SAROJ DUBEY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Karnataka State Government has requested the Union Government for the constitution of a Farmers Welfare Fund for the purpose of providing compensation to farmers in case of crop failure; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal from the Karnataka Government is for setting up of a Farmer's Welfare Fund with an initial corpus of Rs. 10,000 crore for compensating the farmers on account of crop failures.

The matter has been considered. The Central Government is already preparing a modified Crop Insurance Scheme under which the farmers will be duly compensated for failure of crops. In addition, the National Calamity Relief Fund is already there from which assistance is provided to State Governments for giving financial assistance to the farmers in case of crop failures due to natural calamities. In view of this, creation of a separate Farmers Welfare Fund is not considered necessary.

Production of Shrimp

953. SHRI RAHAS BIHARI BARIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total production of Shrimp during last three years;

(b) whether there has been a sharp decline in the production of Shrimp in the country in the last three years;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the steps taken to increase the production of Shrimp with the increase in demand of Shrimp in the international market; and

(e) the details thereof;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) The annual production of shrimp during 1995-96 to 1997-98 is given below:

Year	Shrimp Production (000 tonnes)
1995-96	331
1996-97	361 (Provisional)
1997-98	362 (Provisional)

(b) There has been no decline in the shrimp production during their above period.

(c) Does not arise.

(d) & (e) The steps taken by the Government for increasing the production of shrimp inter alia include:—

(i) development of scientific shrimp farming through Brackishwater Fish Farmers Development Agencies and providing package of tectinical, financial and extension support to shrimp growers.

(ii) encouraging establishment of integrated shrimp farms and support facilities such as seed hatcheries, feed mill, etc. in the Government/public/private sectors.

(iii) human resource development by establishing demonstration-cum-training centres; and

(iv) issue of guidelines outlining measures for development and management of sustainable brackishwater aquaculture practices, etc.

नैफेंड में धन का दुरूपयोग

954.**श्री रामजी लाल**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी,1999 के "राष्ट्रीय सहारा" में "नैफेड" में व्यापक स्तर पर सरकारी धन का दुरूपयोग जांच समिति की रिपोर्ट ने खुलासा किया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां,तो सरकारी धन का दुरूपयोग किस प्रकार और किन मदों में किसके निर्देष पर किन कर्मचारियों के द्वारा किया गया ;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरूद्व क्या कार्रवाई की गई हैं;और

(घ) यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) 06.01.1999 को "राष्ट्रीय सहारा" में नैफेड में धन के कथित दुरूपयोग के संबंध में एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) से (घ) इस विभाग द्वारा की गई जाचं और इस मामले में प्राप्त कुछ अन्य शिकायतों के आधार पर यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरों को आगे भी जांच के लिए भेजा गया । केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने कथित अनियमितताओं के संबंध में नैफेड के कुद प्राधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है ।

जैव उर्वरकों के माध्यम से दूसरी हरित क्रांति

955.**श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में जैव उर्वरकों के प्रयोग से दूसरी हरित क्रांति लाई जा सकती हैं;

(ख) क्या जैव-उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जा सकती हैं;

(ग) यदि हां,तो क्या सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने के संबंध में विचार कर रही हैं;

(घ) यदि हां,तो क्या इसके परिणाम किसानों के अनुकूल होंगे;और

(ड़) सरकार ने जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं तथा पिछले पांच वर्षो के दौरान इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ?